

अरुणाचल बॉर्डर के पास चीन की रेलवे

प्रलम्ब के लिये:

दापोरजो पुल, ससिरी नदी पुल, बोगीबील पुल, हमि वजिय

मेन्स के लिये:

सीमा क्षेत्रों में चीन की बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ और भारत की सुरक्षा

चर्चा में क्यों?

चीन ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेलवे लाइन जो चीन के सचिआन प्रांत (Sichuan Province) को तबिबत में नगिची (Nyingchi) से जोड़ेगी पर कार्य करना शुरू कर दिया है। यह रेलवे लाइन भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है।

Rail to border town

China's planned railway line will run from Lhasa in Tibet to Chengdu, the capital of Sichuan province, connecting both the places to Nyingchi, a city near the Arunachal Pradesh border

- The first segment of the line within Sichuan province, from Chengdu to Ya'an, was completed in December 2018
- Work on the 1,011 km section from Ya'an to Nyingchi, which was formally launched this week, will be finished in 2030



प्रमुख बदि:

- यह [तबिबत स्वायत्त क्षेत्र](#) (Tibet Autonomous Region-TAR) को चीन की मुख्य भूमि के साथ जोड़ने वाला दूसरा ऐसा मार्ग होगा। इससे पहले [कघाई-तबिबत रेलवे लाइन](#) (Qinghai-Tibet Railway Line) द्वारा लहासा को हटिरलैंड क्षेत्र से जोड़ा जा चुका है।

भारत पर प्रभाव:

सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ:

- यह रेलवे लाइन काफी हद तक सीमा क्षेत्र में चीनी सैन्यकर्मियों और सामग्री के परिवहन एवं रसद आपूर्तिकी दक्षता व सुविधा में सुधार करेगी।
- अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास प्रत्यक्ष गतिरोध की स्थितियों में जैसा कि [डोकलाम](#) या हाल ही में [लद्दाख गतिरोध](#) के दौरान देखा गया था, चीन एक लाभप्रद स्थिति में हो सकता है।

पारस्थितिकी से संबंधित चिंताएँ:

- परियोजना लाइन से संबद्ध संवेदनशील पारस्थितिकी वातावरण, भारत के लिये पारस्थितिकी से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न कर सकता है।

भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम:

- भारत, [सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम \(Border Area Development Programme- BADP\)](#) का केवल 10% धन चीन सीमा से लगे बुनयादी ढाँचे में सुधार के लिये खर्च करेगा।
- [सीमा सड़क संगठन \(BRO\)](#) ने अरुणाचल प्रदेश में सुबनसरी नदी के ऊपर सरिफ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में [दापोरीजो पुल \(Daporijo Bridge\)](#) का निर्माण किया। यह भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) तक जाने वाली सड़कों को जोड़ता है।
- हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग ज़िले में नेचिफु (Nechiphu) में एक सुरंग की नींव रखी। यह तवांग के माध्यम से LAC तक सैनिकों की यात्रा में लगने वाले समय को कम कर देगा, जैसे चीन अपने क्षेत्र में होने का दावा करता है।
- BRO पहले से ही अरुणाचल प्रदेश में [से ला दर्रे \(Se La pass\)](#) के तहत एक 'ऑल वेदर टनल' का निर्माण कर रहा है जो तवांग को अरुणाचल व गुवाहाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन (वर्षीय रूप से चीन सीमा के साथ लगे क्षेत्रों से) को रोकने के लिये केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत-चीन सीमा पर बुनयादी ढाँचे के विकास के लिये पायलट परियोजनाओं के रूप में [10 जनगणना शहरों \(Census Towns\) के चयन की सफ़ारिश](#) की है।
- हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में नचिली दबिग घाटी में स्थित [सिसिरी नदी पुल \(Sisseri River Bridge\)](#) का उद्घाटन किया, जो दबिग घाटी को सयिंग से जोड़ता है।
- वर्ष 2019 में भारतीय वायु सेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे पूर्वी गाँव-[वजियनगर \(चांगलांग ज़िले\) में पुनर्निर्मित हवाई पट्टी](#) का उद्घाटन किया।
- वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने अपने नए 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स' (Integrated Battle Groups- IBG) के साथ अरुणाचल प्रदेश और असम में ['हिमविजय' \(HimVijay\) अभियान](#) किया।
- [बोगीबील पुल \(Bogibeel Bridge\)](#) जो भारत का सबसे लंबा सड़क-रेल पुल है, असम में डबिगूढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासिघाट से जोड़ता है। इसका उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था।
 - यह भारत-चीन सीमा के पास के क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों की त्वरित आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत-चीन सीमा क्षेत्र:

- भारत और चीन सीमा साझा करते हैं जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर तक फैली हुई है।
- दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है।
- इसे **तीन क्षेत्रों** में विभाजित किया गया है:
 - **पश्चिमी क्षेत्र:** यह लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश (UT) के अंतर्गत आता है और 1597 कमी. लंबा है।
 - यह दोनों देशों के बीच सबसे अधिक विवादित क्षेत्र है।
 - **मध्य क्षेत्र:** यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और 545 किलोमीटर लंबा है।
 - यह दोनों देशों के बीच सबसे कम विवादित क्षेत्र है।
 - **पूर्वी क्षेत्र:** यह सikkim और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पड़ता है और 1346 किलोमीटर लंबा है।
 - चीन, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है जिसे भारत खारजि करता है।

आगे की राह:

- भारत को अपने हितों की रक्षा के लिये अपनी सीमा के पास चीन में किसी भी नए ढाँचागत विकास के मामले में पर्याप्त रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसे अपने क्षेत्र में दुरगम सीमा क्षेत्रों में मज़बूत बुनयादी ढाँचे के निर्माण की आवश्यकता है ताकि कुशल तरीके से सैन्यकर्मियों एवं रसद की आपूर्तिको सुनिश्चित किया जा सके।

स्रोत: द हिंदू

